

खाली जेब
आपको जिंदगी
के कई मतलब
समझाती है।

- अज्ञात



आतंकी घटनाएं चिंता का विषय

पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस साल पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सीजफायर तोड़ने के मामले में 50 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है। सुरक्षाबलों को बेहद सतर्क रहना होगा। कोरोना के आतंक के बीच उनके लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम देना बेहद मुश्किल है।

मोहन वर्मा।

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर जोर पकड़ रही आतंकी घटनाएं चिंता का विषय हैं। एक ऐसे समय में, जब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, आतंकवाद का सिर उठाना पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीते सोमवार को जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए। उसके एक दिन पहले इसी इलाके में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। हाल के कुछ महीनों में सेना को हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है। पिछले साल जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया और बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की

तैनाती की गई तो लगा कि अब आतंकी संगठनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। कुछ समय तक जमीनी तौर पर ऐसा महसूस भी हुआ। लेकिन पाबंदियों में ढील दिए जाने के साथ ही आतंकीयों की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो गईं। उन्होंने गांव-गांव तक अपना नेटवर्क बना लिया है और ग्रामीणों पर दबाव बनाकर, उन्हें डरा-धमका कर या बंधक बनाकर उनसे जरूरी जानकारियां हासिल करते रहते हैं। हंदवाड़ा में भी उन्होंने ग्रामीणों को बंधक बना लिया था। जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से आतंकी घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है। सेना को जितना नुकसान लॉकडाउन से पहले पूरे साल में हुआ था उससे कहीं ज्यादा लॉकडाउन के 40 दिनों में हो चुका है। सुरक्षाबलों का अनुमान है कि आतंक से संबंधित घटनाओं में वृद्धि

की एक वजह गर्मियों की शुरुआत भी हो सकती है। दरअसल, गर्मियां शुरू होते ही नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास बर्फ पिघलने लगती है। इससे घुसपैठ आसान हो जाती है और कश्मीर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधि बढ़ जाती है। सर्दियों के दौरान घुसपैठ करने के अधिकतर मार्ग बर्फ से ढके रहते हैं। खुफिया सूचना यह है कि लगभग 300 आतंकवादी एलओसी पर पीओके से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इसके लिए पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस साल पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सीजफायर तोड़ने के मामले में 50 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है। कोरोना की आड़ लेकर पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद और अन्य कई आतंकवादियों को जेल से

रिहा कर दिया है।

साथ ही वह गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में बदलाव कर गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की इजाजत दी है। जाहिर है, सुरक्षाबलों को बेहद सतर्क रहना होगा। कोरोना के आतंक के बीच उनके लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। एक तरफ उन्हें खुद को संक्रमण से बचाना है, दूसरी तरफ राष्ट्र रक्षा की अग्रिम पंक्ति वाली भूमिका भी निभानी है। हमें अपनी सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाना होगा, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की चालों का जवाब भी देना होगा।

चिन्ता और डर

अशोक बोहरा।

चिन्ता और डर सुखी जीवन के सबसे बड़े अवरोध होते हैं। हमें अनावश्यक चिंता से बचना चाहिए, चिन्ता और चिन्ता में कोई अन्तर नहीं। चिन्ता मानव को एक बार जलाती है और चिन्ता उसे बार दू बार जलाती है। कई बार अकारण डर व्यक्ति को असमय मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। सुखी जीवन के लिए अपने आहार, विहार, दिनचर्या आदि को व्यवस्थित करना पड़ता है। प्राणशक्ति को प्रबल बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य किया करो। निरोगी काया, घर में संपन्नता, संस्कारी सन्तान, समाज में प्रभाव, अच्छे लोगों के बीच निवास इत्यादि को जरूरी है।

धर्म-दर्शन



सुखी जीवन के लिए आपको योद्धा बनना होगा। योद्धा संघर्षमय जीवन जीता है। मानव जीवन ही वस्तुतः एक संग्राम है। जीवन संघर्षों से कभी नहीं घबराना चाहिए।

संपादकीय

वक्त के अनुसार

इस साल गन्ना किसानों को गन्ने का रकबा कम करके खरीफ की अन्य फसलों— दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और धान का रकबा बढ़ा देना चाहिए। इन फसलों का एक तो भंडारण किया जा सकता है, दूसरे इनकी सरकारी खरीद भी होती है, तीसरे लॉकडाउन में भी इनकी मांग देश-दुनिया में बनी रहेगी। किसानों को समझना होगा कि गन्ना एक नकदी फसल है जिसका न तो भंडारण हो सकता है और न ही इसे भोजन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर यही है कि वे इस वर्ष गन्ने की बुआई का रकबा कम करके चलें अन्यथा आगामी पेरार्ई सत्र में गन्ने को फेंकने या खेतों में ही नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जब हालात सुधर जाएं तो गन्ना किसान फिर अपने गन्ने के रकबे को बढ़ा सकते हैं। कुछ चीनी मिलें गन्ने के सह-उत्पादों से बिजली बनाकर बेच देती थीं पर अधिकांश औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने के कारण बिजली की खपत और मांग भी काफी घट गई है इसलिए बिजली बेचकर होने वाली चीनी मिलों की आमदनी अब ना के बराबर होगी। कोल्हू और खांडसारी उद्योग में भी गन्ने की ज्यादा खपत नहीं हो सकती। चीनी मिलें चीनी के सह-उत्पादों जैसे शीरा, खोई (बगास), प्रैसमड आदि से भी अच्छी कमाई करती हैं। सह-उत्पादों से बायो-फर्टिलाइजर, प्लाईवुड व अन्य उत्पाद बनाकर भी बेचती हैं लेकिन इन सब उत्पादों की मांग भी कम है। भविष्य में इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए गन्ना किसानों को इस साल गन्ने का रकबा कम कर देना चाहिए। गन्ने की बुआई अभी चल रही है पर किसानों को इसे तत्काल सीमित कर देना चाहिए अन्यथा अगले सीजन में ज्यादा दुर्दशा होगी।

चीनी मिलें इसे खरीदने के लिए किसानों को पर्चियां देने में आनाकानी कर रही हैं। इस साल तो हाल खराब है ही, आगामी पेरार्ई सत्र में हालात बेकाबू हो सकते हैं।

कहीं मांग नहीं

चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह।

कोरोना संकट का सीधा प्रभाव अब गन्ना किसानों पर पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण चीनी की मांग और बिक्री काफी घट गई है। चीनी की बिक्री कम होने से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का लगभग 16,000 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया हो गया है। इससे चिंतित उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य के सापेक्ष किसानों को जून तक एक विन्टल चीनी प्रति माह लेने का विकल्प भी दिया है। इस चीनी के मूल्य को इच्छुक किसानों के गन्ना बकाया भुगतान में समायोजित कर दिया जाएगा। पेरार्ई सत्र समाप्ति की ओर है लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 20 प्रतिशत गन्ना खेतों में ही खड़ा है। चीनी मिलें इसे खरीदने के लिए किसानों को पर्चियां देने में आनाकानी कर रही हैं। इस साल तो हाल खराब है ही, आगामी पेरार्ई सत्र में हालात बेकाबू हो सकते हैं। देश में वर्ष 2019-20 में चीनी का उत्पादन 270 लाख टन होने की संभावना है। कोरोना संकट से पहले तक हमारी घरेलू खपत भी लगभग इतनी ही रहने की संभावना थी। इस वर्ष चीनी का प्रारंभिक भंडार 143 लाख टन था। चीनी के निर्यात का लक्ष्य सरकार ने इस वर्ष 60 लाख टन रखा था। बदली परिस्थितियों में केवल 35



से 40 लाख टन चीनी का ही निर्यात होने की संभावना है। गत मार्च से आगामी सितंबर तक देश में चीनी की खपत अपने सामान्य स्तर से 50 से 60 लाख टन कम रहने की आशा है। ऐसे में अगले पेरार्ई सत्र की शुरुआत में ही चीनी का 150 लाख टन से ज्यादा का प्रारंभिक भंडार होगा। यह सामान्य परिस्थितियों में हमारी लगभग सात महीनों की खपत के बराबर है। अगला पेरार्ई सत्र शुरू होने से पहले ही चीनी का इतना बड़ा भंडार होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

दरअसल लॉकडाउन के कारण देश और विश्व

में चीनी की मांग और आपूर्ति का सारा गणित बिगड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। निकट भविष्य में इनके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। चीनी की केवल 25 प्रतिशत खपत घरेलू उपयोग में होती है। बाकी 75 प्रतिशत खपत संस्थानों, भोजनालयों, होटलों, कार्यालयों में या व्यावसायिक उत्पादों— मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम और पेय पदार्थों आदि में होती है। तमाम संस्थाएं और दुकानें बंद होने के कारण यह खपत तेजी से गिर गई है। लॉकडाउन के कारण शादी, समारोह, पार्टियां आदि भी स्थगित हो गए हैं, जिससे चीनी की मांग घट गई है। अगले कुछ महीनों तक चीनी की बिक्री कम होने से भविष्य में गन्ना बकाया भुगतान की समस्या और विकराल रूप ले सकती है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने देश में अधिक चीनी उत्पादन को देखते हुए गन्ने से बड़ी मात्रा में एथनॉल बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए थे।

सोच यह थी कि गन्ने का उपयोग जरूरत के अनुसार चीनी या एथनॉल बनाने में किया जाए तो सारा गन्ना भी खप जाएगा और गन्ना भुगतान का संकट भी नहीं होगा। इस एथनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाने में किया जाना था, इस उम्मीद में कि इससे हमारा कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा।

सूंडीकू बवाल- 5348				****			
8	6						
			5				
	9			7	3		
1		8				2	
		7	4				
6			3			8	
5	7				4		
		8					
			1			6	

सूंडीकू बवाल- 5347 का हल			
9	4	5	3
1	8	6	7
2	7	3	9
6	3	9	1
5	2	4	8
7	1	8	6
4	6	7	5
8	9	1	2
3	5	2	4

अपना ब्लॉग

प्लेग का इतिहास

मोहन। लॉकडाउन के कारण सारे विश्व में आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक सीमित ही रहेंगी। इससे कच्चे तेल की खपत, मांग और कीमतें रसातल में बनी रहेंगी। कच्चा तेल बहुत ज्यादा सस्ता होने के कारण पेट्रोल में एथनॉल मिलाना अभी बिल्कुल लाभकारी नहीं है। लॉकडाउन के कारण पेट्रोल की मांग भी घट गई है लिहाजा चीनी मिलों का गन्ने से एथनॉल उत्पादन करने का विकल्प नहीं बचा है। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें भी बंद हो गईं। अभी कुछ जगहों पर दुकानें खुली जरूर हैं लेकिन शराब की बिक्री और खपत में कमी आई है। इससे चीनी मिलों को डिस्टिलरी से शराब, अल्कोहल आदि बेचकर मिलने वाली राशि भी कम हो गई है। इसके चलते आगामी पेरार्ई सत्र में किसान गन्ना आपूर्ति और भुगतान के बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं।



अब तो अच्छे दिन भी दिखने लगे...